आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव आँचल

वर्ष 47 अंक 43 (प्रति रविवार) इंदौर, 14 जुलाई से 20 जुलाई 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

इंदौर ने बनाया 11 लाख पौधे रोपने का विश्व रिकॉर्ड

इंदौर। *इंदौर ने रविवार को एक नया इतिहास लिख दिया। मध्य प्रदेश शासन के महाअभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत यहां की जनता व जनप्रतिनिधियों ने 12 घंटे में 11 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया था, जिसे तय समय से पहले साढ़े नौ घंटे में ही पूरा कर लिया गया।*

इंदौर की रेवती रेंज पहाड़ियों पर सुबह 7 बजे से शुरू हुआ पौधारोपण का सिलसिला शाम 7 बजे तक चला। लक्ष्य शाम 7 बजे तक 11 लाख पौधे रोपने का था, लेकिन शाम 4.30 बजे तक पौधारोपण का आंकड़ा 12 लाख से ऊपर पहुंच चुका था। इसके बाद भी पौधारोपण जारी रहा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए और अपनी मां के नाम पीपल का पौधा रोपा।एक ही दिन में पौधारोपण का बना रिकॉर्ड-एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में पौधारोपण कर इंदौर ने असम का एक दिन में 9 लाख 26 हजार पौधे रोपने का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के 300 से अधिक सदस्य पौधारोपण स्थलों पर मौजूद रहे और डिजिटल रिकॉर्ड बनाते रहे।देर शाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को इंदौर की इस उपलब्धि का प्रमाण पत्र प्रदान किया। पौधों को बच्चों की तरह बड़ा करें-केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह रविवार दोपहर करीब सवा एक बजे रेवती रेंज पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी उनके साथ थे। पौधारोपण करने पहुंचे लोगों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि जो पौधे रोपे गए हैं, उन्हें बच्चे की तरह बड़ा करना होगा। यही पौधे पेड़ बनकर मां की तरह आपका ध्यान रखेंगे।

गिनीज बुक में हुआ शामिल

ग्रीन सिटी बनेगा इंदौर-शाह

शाह ने कहा, इंदौर स्वच्छता, स्वाद, सुशासन और सहयोग के लिए तो पहचाना जाता ही है, आज से यह शहर एक पेड़ मां के नाम अभियान में सहभागिता के लिए भी पहचाना जाएगा। इंदौर मेट्रो सिटी, क्लीन सिटी, शिक्षा हब तो पहले से ही है, अब यह ग्रीन सिटी के नाम से भी पहचाना जाएगा। शाह ने कहा, मैं मप्र को भारत का फेफड़ा कहता हूं। यहां 31 प्रतिशत वनक्षेत्र है। देश के करीब 12 प्रतिशत वन मप्र में हैं। प्रधानमंत्री ने जब देश की 130 करोड़ जनता से पौधारोपण का आह्वान किया था, तब पता नहीं था कि यह एक महाअभियान बन जाएगा। आज देश का हर व्यक्ति पौधा लगाकर अपनी मां को धरती मां को प्रमाण कर रहा है।

46 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का खजाना, आउटर रत्न भंडार का सामान 6 संदूकों में सील

पुरी (एजेंसी)। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना आज (14 जुलाई) दोपहर 1:28 बजे खोला गया। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि,एएसआई के अधिकारी, गजपति महाराज के प्रतिनिधि और 4 सेवादारों समेत 11 लोग मौजूद रहे।

पुरी मंदिर के मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी ने बताया कि आउटर रत्न भंडार का सामान लकड़ी के 6 बक्सों में शिफ्ट करके सील कर दिया गया है। लेकिन इनर रत्न भंडार का सामान समय कम होने से शिफ्ट नहीं किया जा सका। अब यह काम बहुडा यात्रा और सुना वेशा के बाद किया जाएगा। कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस रथ के मुताबिक दोनों रत्न भंडार के दोनों हिस्सों में नए ताले लगा दिए गए हैं। यहां से मिले कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग की

जाएगी, जिसमें उनके वजन और निर्माण जैसे डिटेल होंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सुपरिंटेंडेंट डीबी गडनायक ने कहा कि मरम्मत के लिए रत्न भंडार का सर्वे होगा। उधर, रत्न भंडार का दूसरा दरवाजा खुलते ही स्क्कपिनाक मिश्रा बेहोश हो गए, हालांकि इसका कारण पता नहीं चल सका। बाद में मंदिर परिसर में ही उनका इलाज किया गया। मंदिर का खजाना आखिरी बार 46 साल पहले 1978 में खोला गया था। 2018 में कोर्ट के निर्देश पर रत्न भंडार को खोलने की कोशिश हुई लेकिन असली चाबियां नहीं मिल सकीं। यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी मेनिफेस्टो में भी रखा था, जिसे सरकार बनते ही पूरा किया।

रत्न भंडार खोलना लोकसभा-विधानसभा चुनाव में मुद्दा बना—12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर चार धामों में से एक है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार खोला जाना बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। इससे पहले 2011 में तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के खजाने को खोला गया था। तब 1.32 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था।

अमेरिका में ट्रम्प पर फायरिंग, कान पर गोली लगी

वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर फायरिंग हुई है। उनके दाएं कान पर गोली लगी है, लेकिन वो सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है।

घटना भारतीय समय के मुताबिक रविवार सुबह 4 बजे की है। तब अमेरिका में शनिवार के शाम करीब 6.30 बज रहे थे। ट्रम्प अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर शहर में चुनावी रैली कर रहे थे। ट्रम्प मंच पर आए उन्होंने बोलना शुरू किया- 'टेक अ लुक एट वॉट हैपंड और फायरिंग की आवाज आनी शुरू हुई। चीख-पुकार मचती है, ट्रम्प चौंकते हुए दायां हाथ कान पर रखते हैं और झुक जाते हैं। इस बीच सुरक्षा गार्ड घेरा बना लेते हैं। ट्रम्प खड़े होते हैं, कान और खून से सने चेहरे के साथ दाई मुट्ठी भींचते हुए कुछ कहने की कोशिश करते हैं। फिर गार्ड उन्हें घेरे में लेते हुए कार में लेकर निकल जाते हैं। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हुई है। 2 गंभीर रूप से घायल हुए। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बताया कि ट्रम्प पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से फायरिंग की गई। एआर क्र-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गईं। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चलीं।

संपादकीय

ट्रंप पर हमला अर्थात बैलेट पर बुलेट का प्रहार

अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में शनिवार शाम करीब 6:15 बजे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर उस वक्त जानलेवा हमला हुआ जबकि वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए वह कम ही होगी, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि बिना हिंसा और खून-खराबे के सरकारें बदल जाती हैं। बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान बात-चीत से निकाल लिया जाता है। बावजूद इसके लोकतांत्रिक देशों में हिंसा बढ़ रही है, जो वाकई चिंता का विषय है। जहां तक पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर हुए हमले की बात है तो जब वो चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तभी फायरिंग हुई और उनके दाहिने कान का ऊपरी हिस्सा जख्मी हो गया। अधिक मात्रा में बहते खून को रोकने ट्रंप ने कान में हाथ लगाया और एक सफल नेता की तरह लोगों को आश्वस्त किया कि कुछ नहीं हुआ है। इसके फौरन बाद ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर अपनी कुशल-क्षेम समर्थकों और शुभचिंतकों को दी और विरोधियों को बतला दिया कि वो ऐसे हमलों से डरने वाले नहीं हैं। वो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। उन पर हमला करने वाला आरोपी युवक उसी वक्त मार गिराया गया। उसकी पहचान भी कर ली गई है। बहरहाल इस दुःखद घटना ने अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया के उन तमाम लोकतांत्रिक देशों के लिए एक सवाल तो छोड़ ही दिया है कि जहां बैलेट से सरकारें बदली जा सकती हैं वहां बुलेट का क्या काम है? आखिर क्या वजह रही होगी कि एक नौजवान को देश के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा चुनाव में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की यूं जान लेने की सूझ पड़ी थी? अमेरिका में इस तरह की यह पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी राष्ट्रपतियों, पूर्व राष्ट्रपतियों और उम्मीदवारों को निशाना बनाया गया और उनकी हत्या कर दी गई। अमेरिका के इतिहास पर सरसरी निगाह डालें तो मालूम चलता है कि यहां की राजनीति में भी हिंसा के स्याह पन्ने जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स को यदि सही माना जाए तो राष्ट्रपति पद पर रहते हुए चार नेताओं की हत्या कर दी जाना कोई मामूली बात नहीं है। इस पर अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी की हत्या की गुत्थी तो आज तक सुलझाई नहीं जा सकी है, जो कि अपने आप में अविश्वसनीय घटना लगती है। इनसे पहले अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की 14 अप्रैल, 1865 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अमेरिका के 20वें राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड की 2 जुलाई, 1881 को गोली मारकर हत्या की गई। इसी तरह से 25वें राष्ट्रपति विलियम मैककिनले को 6 सितंबर, 1901 को गोली मारी गई और उनकी मौत इसी कारण 14 सिंतबर 1901 को हुई। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को नवंबर 1963 में गोली मारी गई थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस हत्या के कारणों का खुलासा आज तक नहीं हो सका, जिसे लेकर समय-समय पर दावे-प्रतिदावे भी किए जाते हैं। इसी तरह से राष्ट्रपति के अनेक उम्मीदवारों को वक्त-वक्त पर बंदूक की गोली का निशाना बनाया गया और उन्हें हलाक कर दिया गया। वैसे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह हिंसा और खून-खराबे की रत्तीभर भी इजाजत नहीं है, लेकिन अफसोस कि देखने में यही आता रहा है कि जब-जब चुनाव आते हैं, किसी न किसी तरह से बुलेट के हिमायती सिर उठाना शुरु कर देते हैं। इसे राजनीतिक हिंसा का नाम दिया जाता है, जबकि इसके पीछे के कारणों की अनदेखी कर दी जाती है। देश और दुनियां के बदलते हालात और नई-नई चुनौतियों को एक कारण माना जाता है, लेकिन इससे आगे भी कुछ है, जिस पर अब विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है। विचार करना होगा कि जिनके हाथों में देश की दशा और दिशा तय करने की ताकत होती है, जब वो चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उनकी भाषा क्या संयमित होती है? क्या वो हथियार उठाने और एक-दूसरे को चुनौती देने जैसे बयानों से बचते हैं? क्या वो वर्ग और जाति में बांटकर लोगों को आपस में लड़ाने और अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने से गुरेज करते हैं?

पोषणयुक्त आहार एवं कुपोषण मुक्त भारत के संकल्प के उजाले

ललित गर्ग

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा भारत सहित पूरे विश्व में भूख, कुपोषण एवं बाल स्वास्थ्य पर समय-समय पर चिंता व्यक्त की गई है। यह चिन्ताजनक स्थिति विश्व का कड़वा सच है लेकिन एक शर्मनाक सच भी है और इस शर्म से उबरना जरूरी है। कुपोषण और भुखमरी से जुड़ी वैश्विक रिपोर्टें न केवल चौंकाने बल्कि सरकारों की नाकामी को उजागर करने वाली ही होती हैं। इस विवशता को कब तक ढोते रहेंगे और कब तक दुनिया भर में कुपोषितों का आंकड़ा बढ़ता रहेगा, यह गंभीर एवं चिन्ताजनक स्थिति है। लेकिन ज्यादा चिंताजनक यह है कि तमाम कोशिशों और दावों के बावजूद कुपोषितों और भुखमरी का सामना करने वालों का आंकड़ा पिछली बार के मुकाबले हर बार बढ़ा हुआ ही निकलता है। इन स्थितियों के बीच भारत में इस गंभीर स्थिति पर नियंत्रण पाने की दिशा में सरकार ने उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। भारत सरकार पोषणयुक्त आहार एवं कुपोषणमुक्त भारत के संकल्प को आकार देने में जुटी है, आजादी के बाद मोदी सरकार ने इस दिशा में उल्लेखनीय सफलता पाई है, जो समस्या से मुक्ति की दिशा में सरकार के संकल्प का उजाला है।

कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिये सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। हालाँकि उनके वित्तपोषण और कार्यान्वयन में अभी भी अंतराल मौजूद हैं। इस मुद्दे को समग्र रूप से संबोधित करने के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक है। कुपोषण की स्थिति तब विकसित होती है जब शरीर विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्त्वों से वंचित हो जाता है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 'कुपोषण मुक्त भारत' सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान शुरू किया था, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान वर्ष 2018 में शुरू किया गया, मिशन का उद्देश्य एनीमिया की वार्षिक दर को एक से तीन प्रतिशत अंक तक कम करना है। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना है, जिसका स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति पर प्रत्यक्ष एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य अपनी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिये खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे भोजन तक पहुँच कानूनी अधिकार बन जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के लिये बेहतर सुविधाएँ प्राप्त करने हेतु 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किये जाते हैं। समेकित बाल विकास सेवा वर्ष 1975 में शुरू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा उनकी माताओं को भोजन, पूर्व स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच और अन्य सेवाएँ प्रदान करना है। इन सब योजनाओं का असर कुपोषण को नियंत्रित करने पर पड़ रहा है।

अंतरिम बजट 2024-25 में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि अमृत काल के दौरान समावेशी विकास के लिए, बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और समग्र विकास में तेजी लाने के लिए एक ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। विजन इंडिया 2047 के प्रयासों को पूरा करने के लिए, फीडिंग इंडिया भूख को कम करने और कुपोषण मुक्त राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से कार्यक्रमों को डिजाइन करने और लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। एक बहुआयामी रणनीति के माध्यम से, फीडिंग इंडिया बड़े पैमाने पर व्यवस्थित हस्तक्षेप, कम आय वाले सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों को सीधे भोजन सहायता और युवाओं के नेतृत्व वाले स्वयंसेवी आंदोलन के माध्यम से कुपोषण के बारे में सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर अपने मिशन को आगे बढ़ाता है। फीडिंग इंडिया एक ऐसे भारत के लिए प्रतिबद्ध है जो आर्थिक रूप से संपन्न हो, नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं को आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करे और जो कुपोषण मुक्त हो। अपनी स्थापना के बाद से, फीडिंग इंडिया ने 30 से अधिक शहरों में 150 कार्यान्वयन भागीदारों के माध्यम से 150 मिलियन से अधिक भोजन उपलब्ध कराया है और 2030 तक वंचित समुदायों को अतिरिक्त 300 मिलियन पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।÷

असल में भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में हर इलाके की खास जरूरतों के हिसाब से अलग व्यवस्था की दरकार है, न कि सब जगह एक ही पैमाने पर बने कार्यक्रम को लागू करना। पिछले कई बरस से यही तरीका अपनाया जाता रहा है। देश से कुपोषण की समस्या जड़ से खत्म करने के लिए नए सिरे से हो रहे प्रयास तीन अहम बातों पर आधारित हैं- बर्ताव में बदलाव, संक्रमण रोकने का प्रबंधन और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले कुपोषण के चक्र को तोड़ना। भुखमरी पर स्टैंडिंग टुगेदर फॉर न्यूट्रीशन कंसोर्टियम ने आर्थिक और पोषण डाटा इकट्ठा किया, इस शोध का नेतृत्व करने वाले सासकिया ओसनदार्प अनुमान लगाते हैं कि जो महिलाएं अभी गर्भवती हैं वो ऐसे बच्चों को जन्म देंगी जो जन्म के पहले से ही कुपोषित हैं और ये बच्चे शुरू से ही कुपोषण के शिकार रहेंगे। एक पूरी पीढ़ी दांव पर है।

कुपोषण के कई रूप हैं, जैसे बच्चों का नाटा रह जाना, कम वजन, एनीमिया प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में समय के साथ सुधार हुआ है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ जैसे गरीब राज्यों में भी सुधार देखा गया। यह किसी विडंबना से कम नहीं है कि कुपोषण के साथ भारत अधिक वजन, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी नई चुनौतियों का भी सामना कर रहा है, जिसे पोषण संबंधी गैर-संचारी रोग भी कहा जाता है। हर पांच में से एक महिला और हर सात में से एक भारतीय पुरुष आज बढ़ते वजन से पीड़ित हैं। शहरी क्षेत्र में दिनोंदिन यह प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास उसकी डाइट पर भी निर्भर करता है। विटामिन, मिनरल, कैल्सियम, प्रोटीन, फाइबर आदि भरपूर डाइट से बच्चे का विकास सही ढंग से होगा ही, वह तंदुरुस्त भी रहेगा। हकीकत ये है कि ज्यादातर माताएं संतुलित आहार व डाइट क्या है? जानती तक नहीं। विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था की उम्र तक बच्चों की डाइट में परिवर्तन होता रहता है।

ग्रामीण क्षेत्रों व मलिन बस्तियों के बच्चों को उचित डाइट नहीं मिल पाती, नतीजतन वे कम वजन व लंबाई और बार-बार बीमारी से जूझते हैं। कई बार कुपोषण की चपेट में भी आ जाते हैं। बढ़ते बच्चों का डाइट चार्ट के अनुसार खानपान जरूरी है। शुरुआत भ्रूणावस्था से हो जाती है। इसके लिए गर्भवती को आयरन, कैल्शियम व फॉलिक एसिड लेना चाहिए। खजूर, गुड़, चना, दूध व दूध से बनी चीजें, चिकन-अंडा, मुरमुरे, अनार, सेब, चीकू, अमरूद, पनीर व दाल का सेवन करें। खूब पानी पीएं। इस उम्र में शिशु को चावल की खीर, दूध में साबूदाना, पिसे हुए पनीर को दलिया मिलाकर खिलाएं। खजूर भी अच्छा है, इसमें मैग्नीशियन, आयरन, फास्फोरस व अन्य पोषक तत्व होते हैं। उम्र बढ़ने के साथ रोटी व हरी सब्जियां भी शुरू कर दें। यह बढ़ती उम्र है, बच्चे को कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए दूध ज्यादा दें। अंडा-पनीर भी कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं। हरी सब्जियां, मौसम के फल व अन्य भोजन खिलाएं। 12 से 13 साल तक बच्चे के भोजन में हर चीज शामिल कर लें।

भारत सरकार एवं वैज्ञानिकों के प्रयास निःसंदेह सराहनीय हैं कि आर्थिक संकट में भी सस्ती वैक्सीन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी कर अपने नागरिकों को सस्ता एवं स्वच्छ उपचार उपलब्ध करा सके तो कुपोषण, भूखमरी एवं बीमारियों से निजात मिल सकेगा। कुपोषण एवं भूखमरी से मुक्ति के लिये भी सरकारों को जागरूक होना होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पोषणयुक्त आहार पर बल दे रहे हैं। कुपोषणमुक्त भारत बनाने की मुहिम में उनके प्रयासों एवं योजनाओं ने उम्मीदें के नये पंख लगाये हैं। आहार की गुणवत्ता को किसी भी व्यक्ति के जीवन में भोजन के सभी स्रोतों के संदर्भ में देखना जरूरी है। चाहे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिया गया भोजन हो, मिड-डे मील के तहत उपलब्ध कराया जा रहा भोजन हो, आइसीडीएस या देश के बाजारों में उपलब्ध खाद्य पदार्थ हो, वर्तमान चुनौती उच्च अनाज और कम प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों की है।

गंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर संभाग में हुए नवाचार अद्भुत-डॉ. यादव

मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान पर केंद्रित इंदौर संभाग की पुस्तिका का विमोचन किया

इंदौर। *मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य शासन के महत्वाकांक्षी अभियान जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर संभाग में हुए कार्यों और प्राप्त उपलब्धियां की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत इंदौर संभाग में हुए नवाचार अदभुत है। इन कार्यों से पर्यावरण संरक्षण एवं जल संवर्धन में मदद मिलेगी।*

डॉ. मोहन यादव ने आज यहां इंदौर एयरपोर्ट के ओल्ड टर्मिनल में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर संभाग में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत हुये कार्यों और प्राप्त उपलब्धियां पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। यह पुस्तिका संभागायुक्त श्री दीपक सिंह की पहल पर तैयार की गई है। इस मौके पर जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर, सांसद श्री शंकर लालवानी, संभागायुक्त दीपक सिंह, कलेक्टर आशीष सिंह, विधायक रमेश मेंदोला, श्री मधु वर्मा तथा गोलू शुक्ला, अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष सावन सोनकर, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉ. महेंद्र सिंह, गौरव रणदीवे सहित अन्य जन प्रतिनिधि मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अन्तर्गत इंदौर संभाग में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की परिकल्पना को जनअभियान का रूप देकर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत जहां एक ओर प्राचीन तथा पुरानी जल धरोहरों को सहेजा और संवारा जा रहा है वहीं दूसरी ओर अनेक जल संरचनाओं का गहरीकरण और जीर्णोद्धार कर उनकी जल क्षमता बढ़ाने के साथ ही उपयोग बनाया जा रहा है। इससे जहां एक ओर जल संरक्षण और संवर्धन होगा, वहीं दूसरी ओर वृहद रूप से वृक्षारोपण कर पर्यावरण सुधार के कार्य भी किये जा रहे हैं। इंदौर संभाग में इस अभियान को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने के लिए अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इसके तहत इंदौर संभाग के इंदौर जिले में 51 लाख पौधों के रोपण का कार्य हाथ में लिया गया है। वहीं झाबुआ जिले में वृहद संख्या में सीड बॉल निर्माण करते हुए विश्व कीर्तिमान रचा जा चुका है। अन्य जिलों में भी कुएं, तालाब, बावड़ी सहित अन्य जल संरचनाओं को पुनर्जीवन देने के व्यापक प्रयास किए गए हैं। संभाग के जिलों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण के कार्य को जनसहभागिता के साथ व्यापक स्वरूप दिया गया है।

500 मीटर पर बनेंगे स्टॉपेज हाथ दिखाकर नहीं रोकना पड़ेगी सिटी बस

यात्री के इशारे पर बस रोकी तो कार्रवाई की जाएगी

इंदौर। स्टापेज के बाहर खड़े यात्रियों को आने वाले दिनों में सिटी बस रोकने हाथ का इशारा नहीं करना पड़ेगा। हर 500-600 मीटर के दायरे में उन्हें स्टापेज मिल सकेंगे। यह स्टॉपेज सर्वसुविधायुक्त होंगे। यह व्यवस्था पहली बार इंदौर में शुरू की जा रही है। प्रदेश में इस तरह की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है।

एआईसीटीएसएल द्वारा शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक सुबह सात से रात 8 बजे तक बसों का संचालन किया जा रहा है। रोजाना लाखों यात्री लाभ उठा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए कई प्रमुख मार्गों, चौराहों पर स्टॉपेज बनाए गए थे। देखरेख के अभाव में स्टापेज जर्जर होकर टूटने लगे हैं। कई जगह भिक्षुकों ने आशियाना बना लिया है। बारिश में यात्रियों पर पानी टपकता है। वहीं, कुछ रूट ऐसे हैं, जहां अस्थाई स्टॉपेज हैं।

नई जगह का सर्वे शुरू-नए स्टॉपेज को कहां स्थापित किया जाएगा, जिससे की यात्री को आसानी रहे। इसका सर्वे किया जा रहा है। उन स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां से यात्री अधिक संख्या में मिलते हैं। बीआरटीएस और सुपर कॉरिडोर को इससे अछूता रखा जाएगा।

जीपीएस से निगरानी होगी- नई व्यवस्था होने के बाद बसों के चालकों- परिचालकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें निर्देश देंगे कि वे बस को तय स्टापेजों पर ही रोक सकेंगे। किसी यात्री के हाथ के इशारे पर बस रोकी तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बसों में लगे जीपीएस से यह देखा जाएगा। एआईसीटीएसएल प्रभारी मनोज पाठक ने जानकारी कि यात्रियों की सुविधा के लिए इस तरह की योजना पर तेजी से काम कर रहे हैं। फिलहाल, स्टॉपेज के लिए स्थान का चयन किया जा रहा है। इसके बाद उनके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।

यात्रियों को मिलेगी सुविधा- ड्राइवरों को पहचानने के लिए छत पर एलईडी बस लोगो रहेंगे। 24 घंटे स्टॉपेज पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। रेट्रो रिफ्लेक्टिव बस स्टॉप नेम बोर्ड लगेंगे। वास्तविक समय की बस जानकारी के लिए एलईडी स्क्रीन, स्थायी विज्ञापन प्रदर्शन, आर्म रेस्ट फोकर्स के साथ बैठने की सुविधा, मोबाइल चार्जिंग सुविधा, सूखे और गीले कचरे के लिए कूड़ेदान, एलईडी लाइट, लकड़ी की बनावट वाली लोवर पैनल छत, मार्गों, बस स्टॉप के बारे में जानकारी प्रदान करने वाला रूट मैप, विज्ञापन प्रदर्शन पैनल, विज्ञापन बोर्ड तथा छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे।

नगर निगम कर रहा सोलर पैनल लगाने की तैयारी

अपनी बिजली से रोशन होंगे पीएम आवास योजना के फ्लैट

इंदौर। मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए तैयार किए गए पीएम आवास योजना के भवनों को भी सोलर पैनल से रोशन किया जाए। पैनल लगने से यहां के रहवासियों को बिजली बिल में राहत मिलेगी। पैनल लगाने का खर्च निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वहन करेगा। निगम के एक अधिकारी ने बताया कि भूरी टेकरी, लिंबोदी, बिजलपुर के समीप, पालाखेड़ी, देवगुराड़िया आदि जगहों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हजारों भवनों का निर्माण किया गया है। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। जहां आवासों का निर्माण किया जा चुका है, वहां लोगों को पजेशन भी दिया है।

सर्वसुविधा युक्त इन भवनों में सैकड़ों परिवार निवास कर रहे हैं। भवनों में रहने वालों को बिजली का बिल अधिक चुकाना पड़ रहा है। रहवासियों की परेशानी को देखते हुए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ने सोलर पैनल लगाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। जल्द ही इसका प्रस्ताव तैयार कर टेंडर बुलाए जाएंगे। पैनल लगने के बाद रहवासियों को भारी भरकम बिजली बिल से निजात मिल सकेगी। बता दें, निगम आगामी दिनों में जल्द स्थित पंपिंग स्टेशन पर भी सोलर पैनल तैयार करेगा, जिससे जल वितरण में आने वाला करोड़ों का बिजली बिल लाखों में तब्दील हो जाएगा। निगम के प्रतिवर्ष लाखों रुपए की बचत भी होगी। स्मार्ट सिटी की मंशा है कि शहरी क्षेत्र के आवासों में भी सोलर पैनल लगाए जाएं, इस पर तेजी से काम चल रहा है।

स्कूल बसें होंगी और ज्यादा सेफ, छत पर लगेगा वाटर टैंक

इंदौर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन लगातार प्रयास करता रहता है। स्कूलों के लिए खरीदी नई बसों का परिवहन विभाग में पंजीयन तभी किया जा रहा है जब उसमें फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम (एफएपीएस) डिवाइस लगी हो। बसों में आग लगने पर इस डिवाइस के कारण सीटों पर पानी का फव्वारा शुरू हो जाएगा और आग पर तत्काल काबू पा सकेंगे। एफएपीएस डिवाइस फायर अलार्म एंड प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसमें बस की छत पर वाटर टैंक बनाना होता है। इसके साथ नाइट्रोजन सिलिंडर भी लगाया जाता है। बस के अंदरुनी हिस्से यानी सीटों के ऊपर पाइप लाइन डालकर उसमें स्प्रिंकलर लगाने होते हैं बस में आगजनी की घटना होने पर यह नाइट्रोजन और पानी को पाइप लाइन में पहुंचाता है और स्प्रिंकलर के माध्यम से तेजी से सीटों पर आता है, जिससे त्वरित गति से आग पर नियंत्रण पा सकते हैं।

सीएम राइज स्कूलों की बसों का नहीं हो पा रहा रजिस्ट्रेशन—इंदौर जिले के 11 सीएम राइज स्कूलों में 10 जुलाई तक 60 से अधिक बसें शुरू होनी थी, लेकिन परिवहन विभाग के नए नियम से पंजीयन नहीं हो पा रहा है। अब तक पांच सीएम राइज स्कूलों में सिर्फ 15 पुरानी बसें ही शुरू की गई हैं। अब खरीदी गई नई बसों में डिवाइस लगवाई जा रही है। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक नरेंद्र जैन ने बताया कि बसों के संबंध में एजेंसी से बात की गई थी। उनका कहना है कि नई बसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आरटीओ प्रदीप शर्मा का कहना है कि बसों में एफएपीएस डिवाइस लगने के बाद ही पंजीयन किया जाएगा।समाया स्कूल बस ट्रांसपोर्ट प्रा.लि. के मैनेजर अभय मिश्रा ने बताया कि 15 बसों में से कुछ पुरानी तो कुछ का रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। जो नई बसें खरीद रहे हैं उनमें एफएपीएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया गया है।

मप्र में सड़क परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं-नितिन गडकरी

भोपाल। देश के केंद्र में स्थिति होने के कारण मप्र का देश के विकास में अहम योगदान रहता है। इसको देखते हुए केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय ने मप्र को सडक़ परियोजनाओं की कई सौगातें दी है। लेकिन प्रदेश में सडक़ परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसको देखते हुए केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडक़री ने मप्र के लोकनिर्माण, वन और राजस्व विभाग के अफसरों को दिल्ली तलब किया है। सोमवार को गडकरी इन अफसरों से योजनाओं के पिछडऩे का कारण जानेंगे और अन्य कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट लेंगे।

गौरतलब हैं कि गडकरी मप्र को लगातार सडक़ परियोजनाओं की सौगात देते रहते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने प्रदेश को सडक़ मार्ग को बेहतर बनाने बड़ी सौगातें दी। केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडक़री ने 499 किलोमीटर लंबाई की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग सडक़ परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। इनकी लागत 8038 करोड़ रुपए है। इसके अलावा पूर्व से कई परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन उनकी प्रगति से केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडक़री संतुष्ट नहीं हैं। कई बार तो वे सडक़ों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठा चुके हैं।

दिल्ली में होगा मंथन

जानकारी के अनुसार केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मप्र में चल रहे नेशनल हाईवेज के काम और केंद्र की मदद से जारी अन्य निर्माण कार्यों की प्रगति से नाखुश हैं। उन्होंने मप्र के अधिकारियों को 15 जुलाई को दिल्ली तलब किया है। लोक निर्माण, वन और राजस्व विभाग के उच्च अधिकारी दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी अधिकारियों से मप्र में चल रहे अपने विभाग से संबंधित प्रोजेक्ट की प्रगति के संबंध में चर्चा करेंगे।

यदि प्रोजेक्ट के निर्माण में रुकावटें सामने आ रही है, तो उन्हें दूर करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। इनमें से कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जिनका भूमिपूजन नितिन गडकरी ने स्वयं मप्र आकर किया था। इस बैठक के बाद मप्र में चले रहे सडक़ निर्माण, रिंग रोड, ओवर ब्रिज आदि प्रोजेक्ट के रफ्तार पकडऩे के आसार हैं। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में होने जा रही बैठक को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पीडब्ल्यूडी, वन और राजस्व अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रोजेक्ट के संबंध में अद्यतन जानकारी ले चुके है। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट की प्रगति से अवगत कराते हुए बताया कि कौन से प्रोजेक्ट में किस कारण से देरी हुई है। इससे पहले तीनों विभागों के अधिकारी आपस में चर्चा कर दिल्ली की बैठक की तैयारी कर चुके हैं।

इनका भी लेंगे फीडबैक

केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च में मप्र में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 3,549.48 करोड़ रुपये मंजूर किए थे। हाइब्रिड वार्षिकी मोड के तहत मध्य प्रदेश के सीहोर और रायसेन जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग -146 बी के 41 किमी खंड को चार लेन करने के लिए 776.19 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। हाइब्रिड एम्प्युटी मोड के तहत भोपाल में राष्ट्रीय राजमार्ग-46 पर आशाराम तिराहा से राष्ट्रीय राजमार्ग-146 पर रत्नागिरि तिराहा तक अयोध्या बायपास के दोनों ओर छह लेन की सर्विस रोड बनाने के लिए 1,238.59 करोड़ रुपये के आवंटन को मंजूरी दी गई थी। इस सभी परियोजनाओं का भी फीडबैक लेंगे।

पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होंगे अफसर

केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडक़री के साथ होने वाली बैठक में सडक़ों के निर्माण में होने वाली देरी का पूरा खाका बनाकर अफसर पहुंचेंगे। इसके लिए अफसरों ने पूरी तैयारी कर ली है। बैठक में जिन प्रोजेक्ट पर चर्चा होगी उनमें विंध्य एक्सप्रेस-वे मप्र में प्रस्तावित 676 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है। यह भोपाल को सिंगरौली से जोड़ेगा। यह कई नेशनल हाईवेज को आपस में जोड़ेगा। नर्मदा प्रगति पथ एक्सप्रेस-वे प्रदेश के 13 जिलों से होकर गुजरेगा। बाद में इसे गुजरात के भरूच या अहमदाबाद तक 150. किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इसकी अनुमानित निर्माण लागत 31,000 करोड़ रुपए है। अटल एक्सप्रेस-वे करीब 20 हजार करोड़ की लागत से कोटा से इटावा तक 415 किलोमीटर लंबाई में बनाया जाएगा। यह एक्सप्रेस-वे बुंदेलखंड व यमुना एक्सप्रेस-वे एवं दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा। बुंदेलखंड विकास पथ उप्र और मप्र को जोडऩे वाला 330 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे है। यह झांसी-ललितपुर-देवास-सागर नेशनल हाईवे के नाम जाना जाएगा। मालवा-निमाड़ विकास पथ जिसे इंदौर-धार अलीराजपुर कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह 450 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे इंदौर मप्र में चल रहे नेशनल हाईवे, आरओबी, रिंग रोड निर्माण प्रोजेक्ट के तार आसार को अलीराजपुर से जोड़ेगा। मध्य भारत विकास पथ मप्र में 746 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित नेशनल हाईवे है। यह परियोजना बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इंदौर में 64 किलोमीटर लंबा पश्चिमी रिंगरोड बनाया जा रहा है। यह महू के पास एबी रोड से सांवेर होते हुए शिप्रा तक सडक़ तक जाएगा। छोला रेलवे ओवर ब्रिज काली परेड से अयोध्या बायपास भोपाल तक बनाया जाना है। पिछले साल केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए 32.44 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। औबेदुल्लागंज से बैतूल व नागपुर को सीधे जोडऩे वाले करीब 150 किमी का फोरलेन निर्माणाधीन है। जबलपुर से दमोह के बीच करीब 101 किलोमीटर की सडक़ की टूलेन से फोर लेन में तब्दील किया जा रहा है। इसकी चौड़ाई 45 मीटर होगी। बमीठा से पन्ना सतना तक एनएच 39 का 98 किमी मार्ग फोरलेन बनाया जाना है।

पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सैद्धांतिक के साथ मिलेगा व्यवहारिक ज्ञान - श्रीमती गौर

भोपाल। पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कृष्णा गौर ने कहा है कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से विद्यार्थियों को सैद्धांतिक के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी मिलेगा। गौर भोपाल के शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविधालय को प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुरुआत कर रही थी।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होने का आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में एतिहासिक दिन है। युवाओं को रोजगारोन्मुखी पाठयक्रम से जुड़कर अपने भविष्य को संवारने का अवसर मिल रहा है। उन्होने कहा कि अग्रेजों के समय की लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में व्यापक बदलाव कर प्रधानमंत्री नरनेंद्र मोदी ने 2020 में नई शिक्षा नीति को लागू किया। युवाओं के भविष्य को संवारने वाली शिक्षा नीती शुरू की। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि हमीदिया कालेज का भोपाल जिला के प्रधानमंत्री कालेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयन होना गौरव की बात है। हमीदिया कालेज भोपाल से विभिन क्षेत्र में प्रदेश और देश का नाम रोशन करने वाली हस्तियों ने शिक्षा प्राप्त की है। हमीदिया कॉलेज का इतिहास गौरवशाली है।

रेलवे यात्री ट्रेनों में 10 हजार से ज्यादा जनरल-स्लीपर कोच बढ़ाएगा

ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ तय क्षमता से दो से तीन गुनी तक

भोपाल। रेलवे ने पिछले चार सालों में ट्रेनों से एक-एक कर जनरल कोचों की संख्या कम कर दी। नई और स्पेशल ट्रेनों में जनरल कोच लगाए ही नहीं। रेलवे ने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए इन कोचों के स्थान पर एसी कोचों की संख्या में दो से तीन गुना तक इजाफा किया। जिन ट्रेनों में तीन से चार थर्ड एसी कोच हुआ करते थे, उनमें 10 से 12 कोच तक कर दिए।

इधर जिन ट्रेनों में चार से छह जनरल कोच लगाए जाते थे, उनमे इनकी संख्या घटाकर दो तक कर दिया गया। इसका असर यह हुआ कि यात्रियों की शिकायत का ग्राफ बढ़ा। इन शिकायतों की समीक्षा की तो ट्रेन में भीड़ की वजह जनरल और स्लीपर कोच की संख्या कम करना सामने आया। अब रेलवे इन कोचों की संख्या बढ़ाने में जुट गया है। इसके तहत देशभर 17 रेलवे जोनों की यात्री ट्रेनों में लगभग 10 हजार से ज्यादा जनरल-स्लीपर कोच लगाने जा रहा है। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के पहले चरण में जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल की 28 ट्रेनों में लगभग 32 जनरल कोच लगाने जा रहा है।

कमाई छोड़, यात्री सुविधा पर जोर- रेलवे बोर्ड ने कोरोना काल के बाद ट्रेनों में लगातार जनरल कोच कम कर एसी कोच

बढ़ाए, ताकि रेलवे की कमाई बढ़े और अधिक से अधिक किराए पर यात्री ट्रेन में टिकट लेकर सफर करे। इसका असर यह हुआ कि जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों को जब इन कोचों में बैठने की जगह नहीं मिली तो वे स्लीपर और एसी कोच में सवार हो गए। टिकट जांच दल ने अपना टारगेट पूरा करने और रेलवे की कमाई बढ़ाने इनसे गंतव्य तक का जुर्माना वसूला और इन्हें कोच में बैठने की पात्रता दे दी, जिसका असर यह हुआ कि ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ तय क्षमता से दो से तीन गुनी तक बढ़ गई। साथ ही यात्रियों की शिकायत का भी ग्राफ बढ़ गया। इस पर रेलवे बोर्ड और पीएमओ ने समीक्षा शुरू कर दी है। सभी रेलवे जोन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे प्राथमिकता से ट्रेनों में जनरल कोचों की संख्या बढ़ाएं।

120 दिन का करना होगा इंतजार-रेलवे अब ट्रेनों में भीड़ की समीक्षा करने में जुटा है। सभी रेल मंडल, अपनी उन ट्रेनों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें पिछले छह माह से लेकर एक साल के दौरान यात्री संख्या कम होने की बजाए बढ़ी है। जबलपुर रेल मंडल में ऐसी लगभग एक दर्जन से ज्यादा ट्रेनें हैं, जिसमें दयोदय एक्सप्रेस, ओवर नाइट एक्सप्रेस, सोमनाथ एक्सप्रेस, गोंडवाना एक्सप्रेस, संपर्कक्रांति एक्सप्रेस, कटरा स्पेशल, यशवंत एक्सप्रेस, महाकौशल एक्सप्रेस, अमरावती एक्सप्रेस हैं । वहीं इन ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या भी कम कर दी गई थी, लेकिन अब जबलपुर रेल मंडल इन ट्रेनों में अतिरिक्त जनरल कोच लगाने जा रही है। जनरल और स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाने के लिए 120 दिन का इंतजार करना होगा। इसकी वजह यह है कि ट्रेनों में निर्धारित कोच संख्या है, जो अभी पूरी है। ऐसे में कई कोच को हटाकर इन्हें लगाया जाएगा, लेकिन हटाने वाले कोचों में 120 दिन तक के आरक्षण हो गए हैं।

मध्यप्रदेश वॉटर स्पोर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की दिशा में प्रयासरत

मंत्री सारंग ने भोपाल की वॉटर स्पोर्ट्स अकादमियों का किया निरीक्षण

भोपाल। *खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि मध्यप्रदेश की वॉटर स्पोर्ट्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बन सके, इस दिशा में हम प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भोपाल और मध्यप्रदेश में जहाँ नर्मदा माँ प्रवाहित हो रही है, उन स्थानों पर वॉटर स्पोर्ट्स के उन्नयन के लिये बहुत कुछ किया जा सकता है।*

श्री सारंग ने इस उद्देश्य से मंगलवार को वोट क्लब, खानूगांव और नीलम पार्क स्थित वॉटर स्पोर्ट्स अकादमियों का निरीक्षण किया। मंत्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश में वॉटर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा काम किया है। मध्यप्रदेश को वॉटर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की दक्षता और भोपाल की खूबसूरत वॉटर स्पोर्ट्स बॉडिस के माध्यम से उच्च स्तर तक ला सकते हैं। मध्यप्रदेश में इसका और उन्नयन कर अग्रसर होने की दिशा में प्रयासरत है, जिससे वॉटर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए सभी खेल मध्यप्रदेश में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकें।

मंत्री सारंग ने कहा कि आने वाले समय में हम एशियन चैंपियनशिप भी करने का प्रयास कर रहे है और उसके साथ-साथ आगामी ओलंपिक में वॉटर स्पोर्ट्स के कुछ खेल भोपाल और प्रदेश में आयोजित हो सके इसका प्रयास किया जा रहा है। इसके लिये जरूरी अंधोसंरचना विकास पर भी कार्य किया जायेगा। मंत्री सारंग ने कहा कि स्कूल, कॉलेज विद्यार्थी भी खेलों के प्रति आकर्षित हो इन दोनों आयामों पर भी प्रयास जारी है। जिससे प्रदेश और देश का नाम रौशन हो सके। खेलों के जरिये युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर मध्यप्रदेश देश में उच्च स्तर प्राप्त कर सके इस दिशा में राज्य सरकार प्रयासरत है। मंत्री सारंग ने निरीक्षण के दौरान कोच और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल सुविधाओं के बारे में जानकारी हासिल की और सुविधाएँ बढ़ाने के संबंध में चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। निरीक्षण के दौरान अपर मुख्य सचिव श्रीमती स्मिता भारद्वाज घाटे, खेल संचालक श्री रवि कुमार गुप्ता और संयुक्त संचालक श्री बीएस यादव सहित अन्य खेल अधिकारी उपस्थित थे।

व्यापारियों की हर समस्या का होगा समाधान-आलोक शर्मा

भोपाल संसद पहुंचे व्यापारियों के बीच, हुआ भव्य स्वागत

भोपाल। भोपाल सांसद आलोक शर्मा मंगलवार को चौक बाजार, जुमेराती, लखेरापुरा, काजीपुरा व सर्राफा क्षेत्र के व्यापारियों के बीच पहुंचे। जहां व्यापारियों ने आलोक शर्मा का पुष्प वर्षाकर भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की है। इस अवसर पर व्यापारियों को संबोधित करते हुए सांसद श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता ने देश में एक स्थाई सरकार दी है। भारत 2047 तक विकसित देशों की श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा। मोदी जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। विकास और जनकल्याण की उनकी सोच ने आज देश को 11वें स्थान से पांचवे नंबर की अर्थव्यवस्था पर ला दिया। पुराने भोपाल में पार्किंग से लेकर व्यापारियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। सांसद शर्मा से व्यापारी एक स्वर में बोले - नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सभी व्यापारियों में खुशी का माहौल है। मोदी के हाथों में देश सुरक्षित है प्रगति भी कर रहा है। स्थायी सरकार से हमें उम्मीदें हैं।

जोरदार स्वागत हुआ

चौक बाजार पर पहुंचे सांसद आलोक शर्मा का मनीष अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल दादा भाई, किशन बंसल, राजेश गर्ग, सतीश जैन, चंद्र मोहन अग्रवाल, सुमित गर्ग, शशि भूषण जौहरी, ओम प्रकाश जरीवाला, गांधी व राजा भाई ने साफा बांधकर, पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर सांसद शर्मा ने व्यापारियों को पौधे वितरित किए और प्रधानमंत्री के आवहन एक पेड़ मां के नाम रोकने का संकल्प दिलाया।

उद्योगों के साथ बिजली संबंधी कार्यों के लिए समन्वय बनाने नियुक्त होंगे रिलेशनशिप मैनेजर

भोपाल। बिजली संबंधी कार्यों के लिए उद्योगों के साथ समन्वय बनाने के लिए रिलेशनशिप मैनेजर नियुक्त किये जायेंगे। बिजली कनेक्शन सहित अन्य समस्याओं का निराकरण समय-सीमा में किया जायेगा। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह बात फिक्की और सी.आई.आई. के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के दौरान कही।

श्री तोमर ने कहा उद्योग जगत को हम सभी जरूरी सुविधाएं देंगे। बिजली की कमी नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा दिये गये सुझावों पर गंभीरता से विचार करेंगे। इस तहर की बैठक लगातार करेंगे। श्री तोमर ने कहा कि यदि हमारे प्रदेश में औद्योगीकरण बढ़ता है, तो हम भी गुजरात की तरह सस्ती बिजली दे पायेंगे। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मनु श्रीवास्तव ने उद्योगों के लिए दिये जा रहे इन्सेंटिव और छूट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सोलर ऊर्जा का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। सोलर ऊर्जा हमें सस्ती मिल रही है। अमन हम किसानों के साथ ही उद्योगों के लिए भी दिन में और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने की स्थिति में हैं। बैठक में फिक्की और सीआईआई के प्रतिनिधियों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। कुछ प्रतिनिधियों ने ऑनलाइन जुड़कर अपनी बातें रखीं। बैठक में मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा हुई। बैठक में एम.डी. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी श्री क्षितिज सिंघल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

राजकुमारी की तरह हुई

राधिका मर्चेंट की विदाई, असली सोने से तैयार लहंगा पहन ससुराल पहुंचीं

इंतजार के बाद आखिरकार राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी शादी के बंधन में बंध चुके हैं। इस कपल ने अपने लंबे रिलेशन के बाद 12 जुलाई को कई बड़ी हस्तियों के सामने एक भव्य समारोह में शादी रचाई। बहुचर्चित इस शादी का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बीते कई महीनों से लगातार शादी से जुड़ी फंक्शन आयोजित किए जा रहे थे, जिसके बाद अब बीते दिन अनंत और राधिका ने सात फेरे लिए। यह भव्य शादी समारोह शुरू से ही इंटरनेट पर छाया रहा और शादी के दिन भी वेडिंग कपल ने काफी सुर्खियां बटोरीं।

अपने इस खास दिन पर वेडिंग कपल ने जमकर सुर्खियां बटोरीं। खासकर अंबानी परिवार की छोटी बहू और अनंत की पत्नी राधिका मर्चेंट लगातार इंटरनेट पर छाई हुई हैं। राधिका अपने वेडिंग लुक को लेकर भी चर्चा बटोर ही रही हैं, साथ ही उनका विदाई लुक भी सोशल मीडिया यूजर्स को बेहद पसंद आ रहा है। आइए जानते हैं कैसा था राधिका विदाई लुक और इसकी खासियत-

बेहद खास था राधिका का विदाई लुक

अपनी शादी के लिए जहां राधिका ने पारंपरिक गुजराती रेड एंड व्हाइट लहंगा पहना, तो वहीं विदाई के लिए उन्होंने सुर्ख लाल रंग का बेहद खूबसूरती लहंगा चोली चुना। विदाई के मौके पर राधिका मशहूर सेलिब्रिटी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया बेहद खूबसूरत लहंगा पहने नजर आईं। इस दौरान वह लाल लहंगे और गोल्डन ब्लाउज में नजर आईं।

असली सोने से बना ब्लाउज

उनके इस आउटफिट का ब्लाउज सिर्फ गोल्डन रंग का ही नहीं, बल्कि इस पर असली सोने के करचोबी का वर्क था। यह कारीगरी पारंपरिक आभो और कच्छ, गुजरात की समृद्ध कपड़ा विरासत से प्रेरित है, जो 19वीं सदी में कलात्मकता को रिफेक्ट करता था।

सोने के वर्क वाले इस ब्लाउज के साथ उन्होंने लाल रंग के मल्टी-पैनल बनारसी ब्रोकेड लहंगा पहना था। स्टाइलिस्ट रिया कपूर के मुताबित यह पहनावा भारत की शाश्वत सुंदरता के प्रति एक श्रद्धांजलि है। वहीं, जूलरी में उन्होंने एक चोकर और हीरे का हार पहना हुआ था, जो मर्चेंट परिवार के खानदानी गहने हैं।

ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या को बच्चन परिवार ने कर दिया अलग! क्या टूटा रिश्ता

फेमस बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी गत 12 जुलाई 2024 को बड़ी ही धूमधूमा से संपन्न हुई है। इस ग्रैंड शादी में बॉलीवुड के कई सेलेब्स शामिल अपने पूरे परिवार के साथ शामिल हुए थे। बॉलीवुड, हॉलीवुड से लेकर साउथ के भी कई मशहूर सेलेब्स ने इस ग्रैंड वेडिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। वहीं बच्चन फैमिली भी अनंत और राधिका को आशीर्वाद देने पहुंची थी। बच्चन परिवार का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, उनकी पत्नी जया बच्चन, बेटा अभिषेक बच्चन, बेटी श्वेता नंदा, दामाद निखिल नंदा, नातिन नव्या नवेली नंदा और नाती अगस्त्य नंदा साथ में पैपराजी को पोज देते नजर आ रहे हैं। बच्चन फैमिली के साथ ऐश्वर्या राय नजर ही नहीं आईं वहीं अमिताभ बच्चन दामाद निखिल नंदा के साथ मुस्कुराते हुए भी नजर आए लेकिन इस फैमिली फोटो में परिवार की बहू ऐश्वर्या राय और पोती आराध्या बच्चन नहीं थीं। दरअसल बच्चन फैमिली के साथ ऐश्वर्या राय नजर ही नहीं आईं। ऐश्वर्या राय अपनी बेटी आराध्या के साथ इस ग्रैंड वेडिंग में शामिल हुई थीं लेकिन उन्होंने बच्चन परिवार के साथ शादी में एंट्री नहीं की। ऐश्वर्या राय और आराध्या ने न तो बच्चन फैमिली के साथ फोटो खिंचवाई और न ही कोई वीडियो बनाया। ऐश्वर्या राय तो बच्चन परिवार के किसी भी सदस्य के साथ मिली ही नहीं। इसके अलावा वह पति अभिषेक बच्चन को इग्नोक करती भी नजर आईं। ऐश्वर्या ने सिर्फ अपनी बेटी आराध्या के साथ पैपराजी को पोज दिए।

लोगों ने बच्चन परिवार को कही ऐसी बात

बच्चन फैमिली के साथ ऐश्वर्या राय को न देखकर लोग भी नाराज हो रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर तरह-तरह के सवाल भी कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है- ऐश्वर्या और उनकी बेटी कहां हैं?

सावन में महादेव को लगाएं इन फलाहारी चीजों का भोग

सावन के महीने का इंतजार लोगों को साल भर रहता है। इस पूरे महीने लोग महादेव की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। इस बार तो सावन का महीना और भी ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस बार सावन का महीना पूरे दो महीने चलने वाला हैं, ऐसे में लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय करेंगे। इन उपायों में लोग व्रत-उपवास भी करते हैं। सोमवार के व्रत में फलाहार खाया जाता है और फलाहार का ही भोग लगाया जाता है। आज हम आपको फलाहार के कुछ ऐसे पकवानों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बनाना बेहद आसान हैं। आप इन पकवानों का भोग महादेव को भी लगा सकते हैं और बाद में व्रत में खुद भी इसका सेवन कर सकते हैं।

कुट्टू की पूड़ी या परांठा

फलाहार बनाने के लिए सबसे पहले आप कुट्टू की पूड़ी बनाने की तैयारी कर लें। अगर आपको पूड़ियां नहीं पसंद हैं तो पराठा भी बना सकती हैं।

व्रत वाले आलू

सावन सोमवार के व्रत में व्रत वाले आलू जरूर बनाएं। इसे खाने से भोजन का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इस सब्जी में नींबू डालना नहीं भूलें।

साबूदाना खिचड़ी

व्रत में साबूदाना खिचड़ी सबसे ज्यादा खाई जाती है। इसे बनाना बेहद आसान होता है और ये खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है। आप महादेव को भी इसका भोग लगा सकती हैं।

साबुदाने की खीर

व्रत में साबुदाने की खीर बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। इसे खाकर आपके घरवाले भी आपकी तारीफ करते थकेंगे नहीं।

साड़ी में दिखना है सबसे अलग तो इन तरीकों को अपनाएं

भारत देश में साड़ी एक ऐसा परिधान है, जिसे हर महिला काफी शौक से पहनती है। साड़ी को किसी त्योहार से लेकर ऑफिस, कॉलेज और शादी की रस्मों में भी पहना जाता है। साड़ी पहनने के लिए कभी किसी खास मौके की जरूरत नहीं होती। बदलते समय में भी एथनिक वियर में साड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है, पर जैसे-जैसे समय बदल रहा है, वैसे-वैसे साड़ी को पहनने का तरीका भी बदल रहा है। नए-नए ट्रेंड के चलते अब महिलाएं और लड़कियां अलग तरीके से साड़ी पहनना पसंद करती हैं। अब

आप अपनी साड़ी को वेस्टर्न लुक भी दे सकते हैं। आइए हम आपको इन तरीकों के बारे में बताते हैं।

साड़ी के साथ बेल्ट

ये देखने में काफी क्लासी लगता है। अगर आप अपनी साड़ी को अलग तरीके से पहनना चाहती हैं तो साड़ी के साथ कमर में बेल्ट लगाएं। ऐसा करने से आपका लुक वेस्टर्न लगेगा।

जैकेट के साथ साड़ी

इस तरह की लंबी या फिर छोटी जैकेट के साथ अगर आप साड़ी पहनेंगी तो आपका लुक अलग दिखेगा। गर्मियों के मौसम में आप कॉटन की जैकेट पहन सकती हैं।

ब्लेजर के साथ साड़ी

अगर आप अपने लुक को फॉर्मल टच देना चाहती हैं तो साड़ी के साथ इस तरह का ब्लेजर पहनें। ये देखने में भी क्लासी लगता है।

क्रॉप टॉप के साथ साड़ी

अपनी साड़ी को अलग लुक देने के लिए उसके साथ ब्लाउज की बजाय आप क्रॉप टॉप पहन सकती हैं। इसके साथ अपनी पसंद का टॉप आप पहन सकती हैं।

श्रग के साथ साड़ी

बैकलेस ब्लाउज के ऊपर अगर आप इस तरह का श्रग डाल लेंगी तो ये आपके साड़ी लुक को अलग दिखाने में मदद करेगा।

सब्जियां लाएंगी चेहरे पर गुलाबी निखार सिंपल स्टेप्स में ऐसे तैयार करें फेस पैक

निखरी और बेदाग त्वचा पाने के लिए लोग कई तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। होम रेमेडीज में भी लोग चंदन पाउडर से लेकर फ्रूट्स तक के फेस पैक बनाते हैं लेकिन सब्जियां भी आपकी स्किन को चमका सकती हैं। चुकंदर से लेकर आलू और खीरा हर रसोई में मिल जाते हैं। ऐसे में आप इनके फैस पैक आसानी से घर पर बना सकती हैं। तो चलिए जानते हैं चुकंदर से लेकर आलू तक के कुछ फेस पैक बनाने का तरीका। ये फेस पैक आपकी स्किन को बनाएंगे लाइट और ब्राइट।

चुकंदर

चुकंदर के हेल्थ बेनेफिट्स के साथ ही स्किन को भी कई फायदे हैं। चुकंदर का पैक डार्क सर्कल और झुर्रियों को भी कम करने में हेल्पफुल रहता है।

इस तरह बनाएं चुकंदर का पैक

एक मीडियम साइज का चुकंदर ग्राइंडर में डालकर अच्छी तरह से पीस लें, अब इसमें गुलाब जल और दही मिलाकर चेहरे पर लगाएं। चुकंदर के इस पैक को 20 मिनट तक लगाने के बाद सादा पानी से चेहरे को धो लें।

आलू का फेस पैक

आलू आपकी स्किन को नमी देता है, आलू के पैक आपके चेहरे की त्वचा सॉफ्ट बनाने के साथ ही ग्लोइंग बनाने में भी सहायक है।

आलू का फेस पैक तैयार करने का तरीका

आलू को पीसकर इसका रस निकाल लें। इसके बाद आलू के रस में शहद मिलाकर चेहरे के साथ ही अपनी गर्दन पर भी अप्लाई करें. आलू के इस पैक को 15 मिनट लगाने के बाद धो दें।

खीरा

गर्मियों में स्किन केयर रूटीन में खीरा शामिल करना एक अच्छा ऑप्शन है। डार्क सर्कल से लेकर आपकी मुरझाई त्वचा को खिला-खिला बनाने के लिए आप खीरे का इस्तेमाल कर सकती हैं।

खीरे का फेस पैक सिंपल स्टेप्स में इस तरह बनाएं

खीरा को छीलकर उसे महीन कद्दूकस कर लें। एलोवेरा की पत्ती से जेल निकालकर खीरे में अच्छी तरह से मिलाकर चेहरे पर लगाएं. ये पैक 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और इसके बाद चेहरा ठंडे पानी से धो दें।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा

क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, ऑर्थोडॉक्स के बदले आउट ऑफ़ बॉक्स यही नई शिक्षा नीति का सार

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस युवाओं की जीवन की दिशा तय करेंगे– मुख्यमंत्री

इंदौर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सन् 2047 तक भारत को संपूर्ण विश्व में हर क्षेत्र में अव्वल रखने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए शिक्षा की नींव मज़बूत होना आवश्यक है। यही कारण है कि सन् 2020 में नई शिक्षा नीति का आगाज़ किया गया। इसमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, ऑर्थोडॉक्स के बदले आउट ऑफ़ बॉक्स को सार मानते हुए नीति निर्माण किया गया। ये गर्व का विषय है कि मध्यप्रदेश में इस नीति को देश में सबसे पहले लागू किया। यह भविष्य के 25 सालों में देश के विद्यार्थियों को विश्व के विद्यार्थियों से स्पर्धा योग्य बनाएगी। यह भी गर्व करने की बात है कि मध्यप्रदेश ने इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा को अपनी मातृ भाषा में पठन पाठन का अवसर यहाँ के विद्यार्थियों को मुहैया कराया है। उद्देश्य सभी वर्ग के लोगो को प्लेटफार्म देखकर समान अवसर उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में आने से पूर्व मैंने उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस ले सभी तयशुदा तयशुदा मानदंडों की पूर्ति संबंधी कैफ़ियत ली थी। मुझे सकारात्मक जवाब सुनकर प्रसन्नता का अनुभव हुआ। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के सुप्रतिष्ठित

संस्थानों के रूप में सारे देश में मध्यप्रदेश का नाम रोशन करने में समर्थ होंगे। मंत्री श्री शाह ने कहा कि इन एक्सीलेंस कालेजों की विशेषता यह है कि इनमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप सभी कोर्स उपलब्ध होंगे तथा ये कालेज सभी संसाधनों से युक्त होंगे। इनसे युवा पीढ़ी को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के ज़रिए विद्यार्थीगणों को कागज़ी शिक्षा नहीं वरन् जीवन में बदलाव के लिए ज़रूरी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। ये प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस युवाओं की जीवन की दिशा तय करेंगे। श्री शाह के हाथों इन कालेजों का शुभारंभ वो भी मालवा की धरती से होना प्रसन्नता और गर्व की बात है। भगवान कृष्ण ने भी मालवा की भूमि में रह 64 कलाओं, 18 पुराणों 14 विद्याओं और चार वेदों की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। छह माह से भी कम समय में इन कालेजों का विधिवत शुभारंभ होना इस सिलसिले में सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने इन 55 कालेजों में शुरू किए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों और लगभग 450 करोड़ रुपयों की लागत से किए गए विकास कार्यों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने अपने स्वागत उद्बोधन में प्रदेश के सभी प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस में संचालित पाठ्यक्रमों, उपलब्ध संसाधनों, संकायों के संचालन के लिए मानव संसाधन और यहाँ विकसित किए जा रहे विद्यावनों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, सांसद कविता पाटीदार, विधायक श्री रमेश मेंदोला, मधु वर्मा, श्री गोलू शुक्ला सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, आईजी श्री अनुराग, पुलिस कमिश्नर श्री राकेश गुप्ता, कलेक्टर श्री आशीष सिंह और बड़ी संख्या में विद्यार्थिगण उपस्थित थे। आरंभ में अतिथियों ने माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समक्ष में दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारम्भ किया। इससे पहले मंत्री श्री शाह ने परिसर में मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी महाविद्यालय के काउंटर का वर्चुअल उद्घाटन तथा भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ का शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस विषयक पुस्तिका का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कालेज आफ एक्सीलेंस पर एक वीडियो फ़िल्म का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में आभार उच्च शिक्षा विभाग के एसीएस श्री केसी गुप्ता ने माना।

देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में फिर शुरू होगा नर्सिंग कोर्स

इंदौर। एक ओर जहां प्रदेश में हुए नर्सिंग घोटाले का मामला सीबीआई जांच के बाद भी अभी तक उलझा हुआ है कई कॉलेजों को गलत तरीके से मान्यता देने को लेकर भी भारी रिश्वत का खेल पकड़ा गया था अब इस मामले में नर्सिंग के कोर्स को बेहतर तरीके से दिये जाने को लेकर देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी 10 वर्ष बाद नर्सिंग कोर्स की परीक्षा आयोजित करवाएगा। इससे पहले विवि प्रशासन को बोर्ड आफ स्टडी और डीन तय करना होंगे।

उच्च शिक्षा विभाग से आदेश मिलने के बाद परीक्षा विभाग इस काम में जुट गया है। जबलपुर स्थित मप्र आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में चल रहे मेडिकल पाठ्यक्रम को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं। वहीं, नर्सिंग कॉलेजों में भी भारी गड़बड़ी और अनियमितताएं सामने आई है। इन गड़बड़ियों और शिकायतों को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने डीएवीवी को निर्देश दिए हैं। करीब हफ्तेभर पहले विवि की स्थाई समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नर्सिंग कोर्स की परीक्षा करवाने पर सहमति बनी। करीब 10 वर्ष बाद विवि में नर्सिंग पाठ्यक्रम जुड़ गए है, लेकिन इन्हें संचालित करने को लेकर नए सिरे से आध्यादेश बनाना होगा। यह काम बोर्ड ऑफ स्टडी गठित होने के बाद ही हो पाएगा।

इसमें डीन नर्सिंग कोर्स के लिए पाठ्यक्रम तय करेगा और बोर्ड परीक्षा से जुड़े नियम व स्कीम बनाने का काम करेगा, जिसमें तीन से चार सदस्य शामिल होंगे। स्थायी समिति की बैठक में निर्णय के बाद विवि अपने दायरे में आने वाले कॉलेजों को नर्सिंग कोर्स संचालिक करने के लिए आवेदन करने का निर्देश देगा। इसके महीनेभर के अंदर विवि कॉलेजों का निरीक्षण कर उन्हें नर्सिंग कोर्स के लिए संबद्धता देगा।

नौलखा से एलआईजी तक जल्द हटाया जा सकता है बीआरटीएस

एलिवेटेड ब्रिज निर्माण के लिए तैयार किए जाएंगे पिल्लर

इंदौर। वाहन चालकों को सुगम और बेहतर ट्रैफिक उपलब्ध कराने के लिए लगातार निर्माण कार्य किया जा रहे हैं। इसी क्रम में शहर में कई ओवर ब्रिज और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। जल्द ही एक एलिवेटेड ब्रिज का काम शुरू किया जाएगा। ब्रिज के लिए एलआईजी चौराहा के समीप बीआरटीएस पर पिल्लर खड़े करने खुदाई कार्य शुरू कर दिया गया है। वहीं, एलआईजी से निरंजनपुर तक दो अन्य चौराहों पर फ्लायओवर ब्रिज प्रस्तावित होने से बीआरटीएस का कुछ हिस्सा तोड़ा गया है। पिल्लर की खुदाई पूरी होते ही नौलखा तक बीआरटीएस को तोड़ा जाएगा, ताकि ब्रिज निर्माण के दौरान किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सके। करीब एक दशक पहले इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष रहे शंकर लालवानी ने शिवाजी वाटिका पर एलिवेटेड ब्रिज को लेकर खाका तैयार किया था। ब्रिज को लेकर सर्वे के साथ राशि स्वीकृति की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद योजना को विराम दे दिया गया। ब्रिज के बदले ट्रैफिक सुधारने प्रशासन ने बीआरटीएस को तैयार कर दिया। इससे बसों का संचालन होने से इस मार्ग पर ट्रैफिक में सुधार आने लगा। लगातार बढ़ते वाहनों की संख्या से बीआरटीएस और उसके बाहर फिर ट्रैफिक का कचूमर निकल गया। इस मार्ग पर कई बार खासकर बारिश और त्यौहारों के जुलूस जलसे में जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। बेहतर ट्रैफिक और जाम से निजात दिलाने एलिवेटेड ब्रिज प्रस्तावित किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री बनने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने ब्रिज को लेकर भूमिपूजन किया था।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)